जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBIT

The Game Is The Science Essentially!

What makes Sooryavanshi particularly intriguing is that the qualities identified by Dr. Niaz are not superficial. They are rooted in the fundamental mechanics of athletic performance

The Beautiful Game

"Royal Heart" Came to Life

तृणमूल और शिव सेना के बाद अब सपा के विघटन की तैयारी है

महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने जैसी शर्मिंदगी भविष्य में नहीं हो, इसके लिए एनडीए ने कमर कस ली है

- **सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में कुल 543 सदस्यों में दो तिहाई बहुमत के लिए 362 सदस्यों की जरुरत है और एनडीए के पास 50 कम, यानि 312 सदस्य हैं, वो भी तृणमूल व शिव सेना के बागी सांसदों का समर्थन मिलने के बाद। राज्यसभा में भी दो तिहाई बहुमत में 9 की कमी है। चर्चा है कि इस कमी को पूरा करने के लिए यूपी में सपा को तोड़ने की तैयारी है।**
- **यूपी में भाजपा की सहयोगी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि सपा का विघटन होगा, 100 प्रतिशत होगा। उन्होंने रामगोपाल यादव का नाम लेकर कहा कि उनके पास उन सांसदों की लिस्ट है, जो एनडीए में आना चाहते हैं।**
- **पता चला है कि 19 जून, शिव सेना के स्थापना दिवस पर शिव सेना के बागी सांसदों का गुट औपचारिक रूप से शिंदे गुट में शामिल हो सकता है।**

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जून। तृणमूल कांग्रेस में विभाजन के बाद, आज शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे (यूबीटी) के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर संसद में एक अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की। बागी सांसदों ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में विलय की मांग की है।

भाजपा का आधिकारिक रुख यह है कि ये क्षेत्रीय दल अपनी आंतरिक कमजोरियों और विरोधाभासों के कारण टूट रहे हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में बड़े पैमाने पर ऐसी अटकलें हैं कि संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के उद्देश्य से भाजपा क्षेत्रीय दलों के विघटनों को प्रोत्साहित कर रही है। परिसीमन विधेयक की हार से पैदा हुई राजनीतिक असहजता के बाद, ऐसी चर्चाएँ हैं कि भाजपा संसद में आवश्यक संख्या जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के बागी समूहों का समर्थन मिलने के बाद भी, एनडीए को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाएगा। लोकसभा की कुल 543 सदस्यीय संख्या में, तृणमूल और शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों का समर्थन मिलने के बाद एनडीए के पास 312 सदस्य होंगे, जबकि दो-तिहाई बहुमत के लिए 362 सदस्यों की आवश्यकता है। इस प्रकार, एनडीए के पास दो तिहाई बहुमत के आँकड़े से करीब 50 सीटें कम रहेंगी।

राज्यसभा की 245 सदस्यीय संख्या (तीन इस्तीफों के बाद घटकर 243) में एनडीए के पास 154 सांसद हैं, जबकि दो-तिहाई बहुमत के लिए 163 सांसदों की आवश्यकता है। यानी, उसके पास दो -तिहाई बहुमत के आँकड़े से 9 सांसद कम हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब समाजवादी पार्टी को भी विभाजित करने की कोशिश की जाएगी?

पिछले कुछ सप्ताहों की इन अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाओं ने एकात्मक राज्य व्यवस्था और एक-दलीय शासन (भाजपा का शासन) के उदय जैसी स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका समाप्त करने के लिए सत्तारूढ़ पक्ष हर तरह की रणनीति अपना रहा है। शिवसेना के वफादार नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि बागी सांसदों को आर्थिक प्रलोभन दिए गए हैं और उन्हें 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव मिले हैं। शिवसेना (यूबीटी) के वफादार नेताओं, संजय राउत, अरविंद सावंत और अनिल देसाई, ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से भेंट की और उनसे आग्रह किया कि मूल पार्टी का पक्ष सुने बिना किसी अलग हुए समूह को मान्यता न दी जाए। शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों में संजय जाधव, ओमराजे निम्बालकर, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, भाऊसाहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटिल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सांसद, जिनमें से कुछ चार्टर्ड विमान से आए, दिल्ली पहुँच चुके हैं। शिंदे गुट के साथ औपचारिक विलय 19 जून, जो शिवसेना का स्थापना दिवस है, को होने की संभावना है। इसी बीच, राजनीतिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेस लगा रहे ट्रैक्टर ई रिक्शा से भिड़े, 6 महिलाओं की मौत

बदायूं, 17 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के उझानी कोतवाली क्षेत्र में बुधवार दोपहर को हाइवे पर रेस लगा रहे ट्रैक्टरों ने एक ई-रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में ई रिक्शा सवार छह महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए है। ट्रैक्टर चालकों को पकड़ लिया गया है।

- **दोनों ट्रैक्टर चालक पकड़े गए।**

जिलाधिकारी राय ने बताया कि पुलिस की जांच में ये पता चला है कि कछला और उझानी के बीच फूलपुर क्षेत्र में बुधवार दोपहर हाईवे पर दो ट्रैक्टर चालक रेस लगा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रैक्टरों ने एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा पर सवार महिलाएं व अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, जहां छह महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया।

ग्रामीणों के अनुसार, मोहल्ला मुरावन नगला निवासी तथा हादसे में घायल हुये डाल सिंह के बेटे कुंवर पाल की शादी 29 जून को होनी है। परिवार की महिलाएं शादी की रस्म के लिए भात मांगने पड़ोस के गठोना गांव जा रहीं थीं।

अब क्या करेंगी, ममता बनर्जी?

राजनैतिक गलियारों में चर्चा है कि ममता बनर्जी के सामने तीन विकल्प हैं, जिनमें से वे कोई एक चुन सकती हैं

- **पहला यह कि वे पार्टी के किसी लोकसभा सांसद से इस्तीफा दिलवाकर लोकसभा चुनाव लड़ें और संसद जाएं, लेकिन अब बंगाल में चुनाव जीतना आसान नहीं है।**
- **दूसरा विकल्प है, राज्यसभा का, लेकिन पार्टी के पास मात्र 80 विधायक हैं। इनके बल पर राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए उन्हें अपने 5 सदस्यों से इस्तीफा दिलवाना होगा, पर इसमें खतरा यह है कि शेष चार सीटें भाजपा को मिलेंगी।**
- **तीसरा व अंतिम विकल्प है कि फिर से जनता के बीच जाएं और तृणमूल कांग्रेस को पुनर्जीवित करें।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जून। अभी से ये अटकलें शुरु हो गई हैं कि एन.डी.ए. सरकार का मुकाबला करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ममता बनर्जी को संसद भेज सकती है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में 16 सांसद चुने जाते हैं। जिन पाँच राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ था, उनके लिए चुनाव इस वर्ष पहले ही हो चुके हैं। इसलिए यदि ममता बनर्जी राज्यसभा में जाना चाहती हैं, तो उन्हें 16 में से कम से कम पाँच सांसदों से इस्तीफा दिलवाना होगा।

वर्तमान स्थिति में राज्यसभा उपचुनाव जीतने के लिए 148 वोटों की आवश्यकता है, जबकि टीएमसी के पास केवल 80 विधायक हैं। इसलिए 80 विधायकों के बल पर राज्यसभा उपचुनाव जीतने के लिए कम से कम पाँच टीएमसी राज्यसभा सांसदों को इस्तीफा देना होगा, जिससे आवश्यक मतों का कोटा घटकर लगभग 50 रह जाएगा। इस स्थिति में टीएमसी एक सीट तो जीत सकती है, लेकिन सबसे अधिक लाभ भाजपा को होगा, क्योंकि वह शेष चार सीटें जीत सकती है। इसलिए यह संभावना कम दिखाई देती है कि ममता बनर्जी राज्यसभा जाएँगी।

ममता बनर्जी के लिए संसद में प्रवेश करने का सबसे आसान रास्ता लोकसभा है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी के 29 लोकसभा सांसद हैं। यदि पार्टी के किसी मजबूत क्षेत्र से चुना गया कोई टीएमसी सांसद इस्तीफा देता है, तो ममता बनर्जी उस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और जीत की उम्मीद कर सकती हैं तथा इस प्रकार वे लोकसभा में पहुँच सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, वह चुनाव टीएमसी के लिए आसान नहीं होगा।

ममता बनर्जी के सामने तीसरा विकल्प यह है कि वे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को फिर से मजबूत करें और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यह समझने की कोशिश करें कि किन कारणों से मतदाता टीएमसी से दूर हुए।

बंगाल में लगभग 40 प्रतिशत मतों के साथ ममता बनर्जी अब भी एक लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। वे इस अवसर का उपयोग करके मतदाताओं के साथ पार्टी के जमीनी संबंधों को फिर से मजबूत कर सकती हैं।

निर्धारित समय पर ही होंगे, विधानसभा चुनाव

चुनाव आयोग के सूत्रों ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से पहले कराने की संभावना को खारिज किया

- **सूत्रों ने स्पष्ट किया कि चुनाव समय पर ही होंगे। जनगणना का दूसरा चरण अवश्य समय से पहले कर लिया जाएगा।**
- **सूत्रों ने यह भी कहा कि 14 जनवरी से हरिद्वार में कुंभ मेला हो रहा है, इसलिए उत्तराखंड के चुनाव सबसे अंत में होंगे।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जून। सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष फरवरी में तय कार्यक्रम के अनुसार ही कराए जाएंगे।

जनगणना और कुंभ के कारण चुनाव निर्धारित समय से पहले कराये जाने की खबरों को स्पष्ट करते हुए सूत्रों ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कुछ राजनीतिक दलों ने कहा था कि जनगणना के दूसरे चरण के कारण विधानसभा चुनाव जल्दी कराए जा सकते हैं। उनका तर्क था कि सरकारी कर्मचारी जनगणना कार्य में व्यस्त रहेंगे, जिससे चुनाव कराना कठिन हो जाएगा। जनगणना कार्य में लगे सरकारी अधिकारियों को अक्सर चुनावी ड्यूटी भी दी जाती है।

लेकिन सूत्रों ने स्पष्ट किया कि चुनाव समय पर ही होंगे। इसके बजाय, जनगणना का दूसरा चरण थोड़ा पहले किया जा सकता है, ताकि सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी के लिए उपलब्ध रह सकें।

जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर के बीच हो रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण किया जा रहा है। दूसरा चरण फरवरी में पूरे देश में होगा, जिसमें व्यक्तिगत आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। इस चरण में जातिगत गणना भी की जाएगी।

इसके अलावा, उत्तराखंड के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बैन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा टेलीग्राम

नई दिल्ली, 17 जून। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को नीट-यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस तेजस करिया की बेंच इस मामले पर कल यानी 18 जून को सुनवाई करेगी।

- **हाईकोर्ट ने टैलिग्राम याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 18 जून को होगी।**

सुनवाई के दौरान, केन्द्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ये आदेश आईटी कानून की धारा 69ए के तहत दिया है। केन्द्र ने टेलीग्राम को कई बार अपना सिस्टम ठीक करने को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी में गैर यादव ओबीसी मतों पर है भाजपा का फोकस

इसके लिए भाजपा ने प्रभावशाली जातीय नेताओं के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाए हैं

- **भाजपा का 2014 से उन छोटी-छोटी जातियों पर जोर रहा है, जो संख्या में कम हैं, पर अपने-अपने क्षेत्र में चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।**
- **इन जातियों में निषाद, कुर्मी, राजभर प्रजापति, पाल, विश्वकर्मा आदि प्रमुख हैं।**
- **उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव न केवल 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होंगे, बल्कि योगी सरकार के 10 साल के काम काज का "लिटमस टैस्ट" भी होंगे।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जून। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति के इर्द-गिर्द घूमती है। चाहे सवर्ण हों, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हों या दलित-जाति, ये राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का केन्द्रीय आधार बनी हुई है। इस संरचना में दलितों के बाद ओबीसी सबसे प्रभावशाली समूह हैं। लेकिन ओबीसी वोट एक समान नहीं है; यह दो भागों में बंटा हुआ है-यादव और गैर-यादव ओबीसी। जहाँ समाजवादी पार्टी (सपा) यादव समुदाय पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है, वहीं, भारतीय जनता पार्टी सुविचारित रुप से गैर-यादव ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। यह रणनीति 2027 विधानसभा चुनावों की उसकी रणनीति का केन्द्र बन चुकी है।

भाजपा अब 2029 लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली "सेमी-फाइनल" लड़ाई की तैयारी में जुट गई है। दिलचस्प बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ सरकार के 10 वर्षों के शासन की परीक्षा भी होंगे।

2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा ने यूपी के राजनीतिक नक्शे को बदलते हुए छोटे-छोटे गैर-यादव ओबीसी समुदायों, जैसे कुर्मी, कोइरी, राजभर, प्रजापति, निषाद आदि, को एकजुट करने में सफलता पाई है। यह गठबंधन 2017 और 2022 की जीतों का मुख्य आधार रहा, जिसने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के पुराने प्रभुत्व को कमजोर कर दिया।

अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, भाजपा ने कई जाति-आधारित नेताओं के साथ रणनीतिक गठबंधन किए हैं। डॉ. संजय निषाद (निषाद पार्टी): केवट/निषाद समुदाय को जोड़ने में अहम भूमिका रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी): राजभर वोट बैंक को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुप्रिया पटेल (अपना दल-एस): कुर्मी राजनीति का प्रमुख चेहरा हैं, जिनका गठबंधन भाजपा की पकड़ मजबूत करता है।

भाजपा की मौजूदा रणनीति छोटे, लेकिन संख्या में महत्वपूर्ण ओबीसी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'शांति समझौते का मसौदा पसंद नहीं आया तो फिर ईरान पर हमला करेंगे'

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप फिर पलटे, फ्रांस में जी-7 समिट में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ईरान के साथ हुई डील "फाइनल" नहीं है

- **ईरान के साथ हुए इस बहुचर्चित शांति समझौते के एमओयू पर एक-दो दिन में ही साइन होने वाले थे, पर, अब यह समझौता ट्रंप के "मूड स्विंग" और इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अस्तित्व की चिंता और इज़रायली मीडिया के मैकनिज़्म में उलझ कर रह गया है।**
- **"पल में तोला पल में माशा" वाले अपने अदांज़ में ट्रंप ने साफ कहा, ईरान को कोई राहत नहीं मिलेगी।**
- **डील को लेकर आरंभ से ही परस्पर विरोधी दावे हो रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस ने कहा कि इज़रायल और लेबनान भी डील से बँधे हैं, वहीं इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, इज़रायल डील की शर्तें मानने को बाध्य नहीं है।**

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जून। पश्चिम एशिया में शांति समझौते का भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना दोहरा रुख दिखाते हुए कहा कि यदि उन्हें समझौते का अंतिम मसौदा पसंद नहीं आया, तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमले शुरू कर देगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच महीनों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दो दिन बाद समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

अगले दो दिनों में जिस एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, वह ट्रंप के बदलते और अनिश्चित स्वभाव, इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक दुविधा और ज़ायोनी मीडिया की भूमिका के बीच फँसा हुआ दिखाई देता है।

फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता अभी "फाइनल नहीं" है।

ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता "फाइनल नहीं" है। उन्होंने इसे केवल एक "मैचोरैन्डम ऑफ "अन्डरस्टैन्डिंग" बताया। उन्होंने कहा, "नहीं, यह अंतिम नहीं है। यह एक एमओयू है। अगर मुझे यह पसंद नहीं आया तो हम फिर उन पर गोलीबारी करेंगे, उनके सिर पर बम गिराएंगे। अगर मुझे यह पसंद नहीं आया, अगर उन्होंने ठीक व्यवहार नहीं किया, तो हम फिर से उनके ऊपर बम बरसाना शुरू कर देंगे।"

अपनी राशि मिथुन (जेमिनी) की तरह ट्रंप ने एक ओर सख्त बयान दिया, तो दूसरी ओर समझौते की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एमओयू में तत्काल प्रतिबंध हटाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक मजबूत और सकारात्मक कदम है। जी-7 सम्मेलन में उन्होंने कहा, "यह बहुत मजबूत समझौता है। किसी को ठीक-ठीक नहीं पता कि इसमें क्या है, लेकिन यह बहुत मजबूत है और अधिकांश लोग इससे खुश दिखाई देते हैं।" उन्होंने बाजारों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को भी समझौते पर भरोसे का संकेत बताया।

इस बीच तेहरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद से इज़रायल ने लेबनान युद्धविराम का 84 बार उल्लंघन किया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि ये हमले जारी रहे तो वह "कड़ा जवाब" देगा। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब दक्षिणी लेबनान में इज़रायली हमलों में चार लोगों की मौत हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से लेबनान के मामले में "अधिक जिम्मेदारी" दिखाने को कहा।

टैंकरट्रैकर्स के अनुसार, ईरानी तेल लेकर जा रहा तीसरा टैंकर ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी रेखा को पार कर चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में प्रतिबंधों में राहत, ईरान की फ्रीज़ की हुई संपत्तियों की रिहाई और लेबनान से इज़रायल की वापसी शामिल होनी चाहिए।

वॉशिंगटन और तेहरान 19 जून को एक अंतरिम समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़रायल युद्ध को समाप्त करना है।

हालाँकि समझौते के कई महत्वपूर्ण विवरण अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस एमओयू से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य लंबित मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता का रास्ता बनने की उम्मीद है। समझौते का पूरा टैक्स्ट अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

अमेरिका और ईरान संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते के करीब पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सतर्क रुख अपनाते हुए कहा, "हमारे पास टूटे हुए वादों का इतिहास है... समझौतों को तोड़े जाने का इतिहास है। यह सब हमारी याद में मौजूद है।"

अमेरिका और ईरान ने वर्चुअल माध्यम से एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे अंतिम समझौते की उम्मीद बढ़ी है। लेकिन एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात पर "गंभीर" संदेह है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर आवश्यक रियायतें देने को तैयार होगा।

यह भी कहा जा रहा है कि एक्सियोस ऐसी खबरें प्रकाशित कर रहा है जिनसे यह समझौता कमजोर पड़ सकता है। जानकार सूत्रों के अनुसार, एक्सियोस को इज़रायल समर्थक ज़ायोनी समूहों से भारी वित्तीय सहायता मिलती है और वह इज़रायल के रणनीतिक हितों की रक्षा और बढ़ावा देने की दिशा में काम करता दिखाई देता है। घरेलू दबाव का सामना कर रही नेतन्याहू सरकार मौजूदा युद्ध जैसी स्थिति को बनाए रखना चाहती है और प्रस्तावित समझौते के पक्ष में नहीं है।

हालाँकि ट्रंप ने कई बार इज़रायली प्रधानमंत्री के प्रति अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह ज़ायोनी लॉबी के दबाव की पूरी तरह अनदेखी करने की स्थिति में नहीं हैं।

ब्लूमबर्ग द्वारा प्राप्त एक ज्ञापन के अनुसार, अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण के लिए परियोजनाओं पर काम करेंगे, जिसे युद्ध क्षतिपूर्ति का हिस्सा माना जा रहा है। ज्ञापन में कम से कम 300 अरब डॉलर की सहायता राशि का उल्लेख किया गया है।

हालाँकि दोनों पक्षों का कहना है कि शुक्रवार से होर्मुज़ जलडमरूमध्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)